VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(02 April 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने का मुद्दा
- सुप्रीम कोर्ट ने 'उधार सीमा' को लेकर केरल के मुकदमे को संविधान पीठ के पास भेजा
- RBI द्वारा 'डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA)' की स्थापना का विचार

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने का मुद्दा:

चर्चा में क्यों है?

- भारतीय राज्य, अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को फिर से जोर देने के लिए हाल के हफ्तों में चीन के बढ़ते दावों के बीच, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 विभिन्न स्थानों के नामों की एक सूची जारी की है। भारत चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने को खारिज करता रहा है, यह कहते हुए कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न अंग है और "काल्पनिक" नाम रखने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आता है।

भारत के विदेश मंत्री का इसको लेकर जवाब:

- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश, जिसे वह 'दक्षिण तिब्बत' के रूप में दावा करता है, में 30 अन्य स्थानों का नाम बदलने के जवाब में कहा कि “अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा”।

- डॉ. जयशंकर ने कहा कि “अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य था, है और रहेगा। नाम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता"।
- उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में तैनात है।
- उल्लेखनीय है कि पहले भी विदेश मंत्रालय ने चीन के नाम बदलने की प्रक्रिया को खारिज कर दिया था।

चीन के इस कवायद के संभावित कारण:

- उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा यह कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के बाद हुआ है जहां उन्होंने 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी रणनीतिक महत्व की सेला सुरंग का उद्घाटन किया था। यह सुरंग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और इससे सीमांत क्षेत्र में सैनिकों की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित होगी।
- साथ ही अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने वाले बयान पर भी चीन में घर्षण दिखायी दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 9 मार्च को कहा था कि "अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में

मान्यता देता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार सैन्य या नागरिक घुसपैठ या अतिक्रमण द्वारा क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के किसी भी एकतरफा प्रयास का अमेरिका दृढ़ता से विरोध करता है"।

इसका कवायद का सीमा विवाद पर क्या असर होगा?

- हालांकि इस प्रतीकात्मक संकेत का सीमा विवाद पर जमीनी स्तर पर बहुत कम वास्तविक प्रभाव होने वाला है, लेकिन साथ ही, यह यह भी दर्शाता है कि सीमा पर स्थिति, जिसे भारत ने "स्थिर लेकिन अप्रत्याशित" बताया है, कैसी है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सुप्रीम कोर्ट ने 'उधार सीमा' को लेकर केरल के मुकदमे को संविधान पीठ के पास भेजा:

चर्चा में क्यों है?

- सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 145(3) के संदर्भ में राज्य की उधार लेने की क्षमता पर लगाई गई सीमा को चुनौती देने वाले केरल राज्य द्वारा भारत संघ के खिलाफ दायर मुकदमे को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया।
- हालांकि, साथ ही, जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त उधार के लिए राज्य द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला क्या है?

- केरल ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, यह तर्क देते हुए कि राज्य की उधार लेने की शक्तियों पर

केंद्र की रोक संघवाद पर हमला है और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के टूटने के लिए उत्प्रेरक है।

- केरल ने तर्क दिया था कि उधार लेने की सीमा राज्यों द्वारा तय की जानी चाहिए। जबकि संघ ने तर्क दिया था कि राज्य में राजकोषीय घाटे का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसके कारण उसका व्यय उसकी आय से कहीं अधिक था।

संविधान पीठ के समक्ष किन प्रश्नों को भेजा गया है?

- "राजकोषीय विकेंद्रीकरण" भारतीय संघवाद का एक पहलू है और क्या राज्यों पर शुद्ध उधार सीमा तय करने वाले केंद्रीय नियम, संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन है?
- संवैधानिक पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 131 और 293 की व्याख्या से जुड़े व्यापक प्रश्नों को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 131, केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों पर SC का अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है, जबकि अनुच्छेद 293 राज्यों को बाहरी उधार लेने की शक्ति देता है और संघ इसे किस हद तक विनियमित कर सकता है, इससे जुड़ा है।

- संविधान पीठ से यह जांच करने की भी मांग की कि क्या केंद्र के उधार प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक को "सार्वजनिक ऋण प्रबंधक" के रूप में सौंपी गई भूमिका के साथ टकराव में हैं?
- इसके अतिरिक्त, राजकोषीय नीति से संबंधित न्यायिक समीक्षा के दायरे की जांच भी संविधान पीठ द्वारा की जाएगी।
- अंत में, सवाल यह भी है कि क्या वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र के लिए राज्यों के साथ पूर्व परामर्श करना अनिवार्य है?

सर्वोच्च न्यायालय का इस मामले में अंतरिम निर्णय क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्नों को संविधान पीठ को संदर्भित करने के आलावा केरल सरकार को किसी अन्य प्रकार का अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है।
- उल्लेखनीय है कि पीठ को अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करने की केरल की क्षमता पर संदेह है। इसने केंद्र सरकार को केरल के लिए शुद्ध उधार सीमा पर रोक को उठाने या राज्य को तत्काल आधार पर ₹26,226 करोड़ उधार लेने में सक्षम बनाने का निर्देश देने वाला कोई भी न्यायिक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- अदालत ने कहा कि "यदि राज्य ने अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण वित्तीय कठिनाई पैदा की है, तो ऐसी कठिनाई को एक अपूरणीय क्षति नहीं माना जा सकता है जिसके लिए संघ के खिलाफ अंतरिम राहत की आवश्यकता होगी... यह कानून में एक बुरी मिसाल कायम कर सकता है जो राज्यों को राजकोषीय नीतियों का उल्लंघन करते हैं और फिर भी सफलतापूर्वक अतिरिक्त उधार का दावा करने में सक्षम बनाएगा"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

RBI द्वारा 'डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA)' की स्थापना का विचार:

चर्चा में क्यों है?

- बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक, 'अवैध ऋण ऐप्स' की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए, एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA) स्थापित करने पर विचार कर रहा है।
- प्रस्तावित एजेंसी डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स के सत्यापन को सक्षम करेगी और सत्यापित ऐप्स का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखेगी।

'डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA)' क्या है?

- एक बार स्थापित होने के बाद DIGITA को डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रस्तावित एजेंसी का लक्ष्य डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स को सत्यापित करना और सत्यापित ऐप्स का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखना होगा।

- जिन ऐप्स पर DIGITA के 'सत्यापित' हस्ताक्षर नहीं हैं, उन्हें कानून प्रवर्तन के उद्देश्य से अनधिकृत माना जाना चाहिए, यह डिजिटल क्षेत्र में वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जांच बिंदु के रूप में काम करेगा।
- यह संपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया बढ़ते डिजिटल ऋण क्षेत्र के भीतर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा करने में मदद करेगी, जिसमें हाल के दिनों में धोखाधड़ी गतिविधियों और बेईमान प्रथाओं में वृद्धि देखी गई है।

'अवैध ऋण ऐप्स' पर रोक लगाने की RBI की वर्तमान पहल:

- RBI ने आईटी मंत्रालय को Google के व्हाइटलिस्टिंग के लिए 442 डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की एक सूची प्रदान की है।
- उल्लेखनीय है कि सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक, Google ने अपने ऐप स्टोर से 2,200 से अधिक डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स हटा दिए।
- वित्त मंत्रालय के तहत आरबीआई और वित्तीय सेवा विभाग के अनुरोधों के बाद, Google अब केवल आरबीआई-विनियमित संस्थाओं (RE) द्वारा या RE के साथ साझेदारी में तैयार ऐप्स को ही 'प्ले स्टोर' पर अनुमति देने वाली नीति लागू करता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQ:

Q.1. सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को राज्य की उधार लेने की क्षमता पर लगाई गई सीमा को चुनौती देने वाले केरल द्वारा भारत संघ के खिलाफ दायर मुकदमे को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। संविधान पीठ को संदर्भित प्रश्नों में शामिल है/हैं:

1. क्या केंद्र के उधार प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक को "सार्वजनिक ऋण प्रबंधक" के रूप में सौंपी गई भूमिका के साथ टकराव में हैं।
2. क्या वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र के लिए राज्यों के साथ पूर्व परामर्श करना अनिवार्य है?

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)

Q.2. हाल में RBI ने आईटी मंत्रालय को Google प्लेस्टोर पर व्हाइटलिस्टिंग के लिए कितने डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की सूची प्रदान की है?

(a) 2200

(b) 2023

(c) 5000

(d) 442

Ans. (d)

Q.3. हाल ही में चर्चा में रहे 'डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारतीय रिजर्व बैंक 'अवैध ऋण ऐप्स' की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए इस एजेंसी को स्थापित करने पर विचार कर रहा है।
2. इसको डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की मूल्यांकन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)

Q.4. हाल ही में चर्चा में रहे 'संविधान के अनुच्छेद 131' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

(a) अनुच्छेद 131, केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों पर SC का अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है।

(b) अनुच्छेद 131, राज्यों को बाहरी उधार लेने की शक्ति देता है और संघ इसे किस हद तक विनियमित कर सकता है, इससे जुड़ा है।

(c) अनुच्छेद 131, राज्य की उधार लेने की क्षमता पर लगाई गई सीमा को निर्धारित करता है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही नहीं हैं।

Ans. (a)

Q.5. हाल ही में 'चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने' की कवायद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. चीन द्वारा दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों के नामों बदलने की एक सूची जारी की गयी है।
2. चीन द्वारा यह कवायद प्रधानमंत्री की हाल की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के बाद हुआ है जहां उन्होंने रणनीतिक महत्व की सेला सुरंग का उद्घाटन किया था।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b)